राजस्थान के सीमा क्षेत्रों में सैन्य अभ्यास के दौरान सेना को पानी सप्लाई करने के लिए पृथक व्यवस्था

3236. **श्री बृद्धि चन्द्र जैन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश की सेना शीत-काल के दौरान राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर के सीमावर्ती रेगिस्तानी क्षेत्रों में सैन्य अभ्यास करती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन रेगिस्तानी क्षेत्रों में, जहां कि पानी की भारी कमी है, राज्य की क्षेत्रीय ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के पानी का उपयोग करके सेना वहां के लोगों का कष्ट और अधिक बढ़ा देती है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सेना को समुचित जल सप्लाई की पृथक व्यवस्था करने के लिए केन्द्रीय सरकार अपनी स्वयं की योजनाएं बनाएगी ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) (क) : जी, हां।

(ख) जब सेनाएं अभ्यास के लिए आती हैं तो वे सिविल प्रशासन की सहमति से स्थानीय स्रोतों से पानी लेकर अस्थाई जल व्यवस्था का प्रबन्ध करती हैं। इस प्रकार की जल व्यवस्था से स्थानीय लोगों को होने वाली कठिनाइयों के बारे में रक्षा मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं है।

(ग) ये अभ्यास प्रतिवर्ष एक ही स्थान पर नहीं होते हैं। इसलिए अभ्यास के लिए बाहर जाने वाली सैन्य टुकड़ियों के लिए स्थायी जल की व्यवस्था करना संभव नहीं होगा।

विभिन्न वस्तुओं के मूल्य

3337. **श्री रामविलास पासवान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978-79 में पेट्रोल, डीजल, सीमेंट, उर्वरक, कोयला, गैस, मिट्टी का तेल, दालों, तिल-हनों तथा चीनी के क्या मूल्य थे ; और

(ख) उपर्युक्त वस्तुओं के इस समय क्रमशः मूल्य क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :

थोक मूल्य सूचकांक
(1970-71 = 100)

	1978-79 (वित्तीय वर्ष औसत)	25-2-84 (अ) (नवीनतम उपलब्ध)
1	2	3
दालें	247.1	388.0
तेलहन	158.9	326.7
चीनी	146.6	236.5
पेट्रोल	299.1	526.6
मिट्टी का तेल	235.0	343.2

1	2	3
हाई स्पीड डीजल तेल	164.0	414.9
लाइट डीजल तेल	269.1	800.1
सीमेंट	196.6	433.1
उर्वरक	175.2	264.4
कोयला	212.2	641.9
कच्चा पेट्रोलियम (क्रूड) और प्राकृतिक गैस	802.9	1739.5

(अ) अनन्तिम

Financial Assistance to Weaker Sections under 20-Point Programme

3338. SHRI ARJUN SETHI :
SHRI KRISHAN PRATAP SINGH :

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the details regarding the financial assistance provided to the weaker sections under the 20-Point Programme to the States, during 1983-84 ;

(b) what are the targets, category-wise, for providing financial assistance to the States to the weaker sections during 1983-84 ; and

(c) whether the grant sanctioned in this regard were properly utilised for the purpose so far as the question of performance under the 20-Point Programme is concerned ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHANA POOJARY) : (a) to (c). Public Sector Banks have been advised to endeavour to enlarge the flow of credit to the viable ventures of the weaker sections of the community. A concept of weaker sections, comprising small and marginal farmers, landless labourers, share croppers, tenant farmers, Scheduled Castes and Scheduled Tribes, D.R.I. Scheme beneficiaries, I.R.D.P. beneficiaries, artisans and cottage and village industries has been evolved within the priority sectors and the public sector banks have been asked to ensure that this group accounts for not less than 25 per cent of their total priority sector credit by March 1985. As per quick estimates, weaker sections had received Rs. 2475 crores involving 99.3 lakh borrowal accounts or 19.3 per cent of the priority sector advances of the public sector banks by September 1983. Banks are participating in schemes such as I.R.D.P. or those formulated by SC/ST Development Corporation in the States. In other areas of credit deployment to weaker sections also, the banks are evolving specific programmes, identifying beneficiaries and extending credit assistances. State-wise details of public sector banks' priority sector advances to Weaker sections have not yet become available. Complaints about various aspects of the implementation of the policies are received from time to time. These are investigated for corrective action, whenever called for.